



उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

(संस्था संस्थापक श्रद्धेय पं. मुरारी लाल शर्मा-अमर रहें!)



पंजी0 संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ-226005

नीलेश रंजन राव परमार

प्रदेश अध्यक्ष
+91-8299684352

web.www.lekhpal.wordpress.com
Email : lekhpal.up@gmail.com

राहुल पटेल

प्रदेश महामंत्री
+91-7510047049

प्रदेश उपाध्यक्ष गण

प्रवेन्द्र सिंह

(पश्चिमी जोन)
मो. 9927774580

अभिषेक कुमार मिश्रा

(मध्य जोन)
मो. 7905001655

सुबोध कुमार सिंह

(भूतपूर्व सैनिक नौ सेना)
(पूर्वी जोन)
मो. 9598892105

प्रदेश संगठन मंत्री गण

भूपेन्द्र चौधरी

(पश्चिमी जोन)
मो. 9410215684

सुजीत कुमार

(मध्य जोन)
मो. 9453993099

आशुतोष पाण्डेय

(पूर्वी जोन)
मो. 9519140580

प्रदेश कोषाध्यक्ष

दिपांशु भारद्वाज

मो. 9149389796

प्रदेश लेखा परीक्षक

योगेश कुमार यादव

(भूतपूर्व सैनिक वायु सेना)
मो. 9026766144

पत्रांक... 7/महामंत्री
सेग में,

दिनांक... 09/06/2026

मा० विशेष सचिव महोदय

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषय - आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के लखनऊ आगमन पर समस्त संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में लेखपाल संघ को प्रतिभाग हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, सादर अवगत करना है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अल्प कर्मचारी संगठनों में सबसे बड़ा संगठन है जो कि प्रदेश में 36837 लेखपालों का प्रतिनिधित्व करता है, आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का फिनांश 22/06/2026 व 23/06/2026 को लखनऊ में समस्त संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित बैठक से पूर्व फिनांश 10/06/2026 को नवीन भवन उ० प्र० समिबालय लखनऊ में फिनांश संख्या-वे०आ०-2-387/दस-2026 फिनांश 08 जून, 2026 के माध्यम से निर्धारित संघों के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को विचार/मत/सुझाव प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया गया है, परन्तु उक्त बैठक में लेखपाल संघ को विचार/मत/सुझाव हेतु आमंत्रित न किया जाना खेदजनक है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि फिनांश 10/06/2026 को नवीन भवन उ० प्र० समिबालय लखनऊ में व फिनांश 22/06/2026 व 23/06/2026 को लेखपाल संघ को प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। संस्था की पूर्ण आभारी रहेगी।

कलिंग नगर -

पत्र सं० - वे०आ०-2-387/दस-2026 फिनांश 08 जून, 2026।

प्रतिनिधि -

सादर सूचनाएँ व आभारपूर्ण कृपियाँ हेतु।

1- मा० प्रमुख सचिव राजेश, उ० प्र० शासन, लखनऊ।

2- मा० प्रमुख सचिव वित्त, उ० प्र० शासन, लखनऊ।

09/06/2026
राहुल पटेल
प्रदेश महामंत्री

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-वे०आ०-2-387/दस-2026
लखनऊ: दिनांक ०४ जून, 2026

श्री शिव गोपाल सिंह, अध्यक्ष, उ०प्र० सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ लखनऊ, उ०प्र०।	श्री अर्जुन देव भारती, अध्यक्ष, उ०प्र० सचिवालय संघ,, उ०प्र०।	इं० हरिकिशोर तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०।	श्री एस०पी० तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०।
श्री जे०एन० तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०।	श्री सुरेश कुमार रावत, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०।	श्री वी०पी० मिश्र, अध्यक्ष, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उ०प्र०।	श्री रिजवान अहमद सिद्दीकी, अध्यक्ष, राजकीय वाहन चालक महासंघ, उ०प्र०।
श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० सरकार स्टेनोग्राफर्स महासंघ उ०प्र०।	श्री उग्रसेन सिंह, अध्यक्ष, उ०प्र० सांख्यिकीय सेवा परिसंघ उ०प्र०।	इं० एन०डी० द्विवेदी, अध्यक्ष, उ०प्र० डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ।	श्री कृतार्थ सिंह, अध्यक्ष, उ०प्र० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन।
श्री रामराज दूबे, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ।	श्री कमल अग्रवाल, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ।	इं० हृदय नारायण मिश्र, अध्यक्ष, उ०प्र० डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ।	श्री दिवाकर सिंह, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन।
श्री संदीप कुमार पाण्डेय, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन।	श्री राम लाल यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० कर्मचारी महासंघ।	श्री जे०पी० पाण्डेय, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन।	श्री अजय सिंह, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ।
श्री अरविन्द कुमार वर्मा, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०।	श्री हरिशरण मिश्र, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी एसोसिएशन, उ०प्र०	श्री अशोक कुमार सिंह, प्रान्तीय अध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ।	श्री संजीव पाण्डेय, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०।

महोदय,

कृपया सदस्य सचिव, आठवां केन्द्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 27 मई, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का दिनांक 22.06.2026 एवं 23.06.2026 को

लखनऊ आगमन प्रस्तावित है जिसमें समस्त संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया जाना है।

2- अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित बैठक से पूर्व केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित 18 प्रश्नों की प्रश्नावली (वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 10.03.2026 के साथ संलग्न) के संबंध में दिनांक 10.06.2026 को अपराह्न 02:00 बजे पारिजात सभाकक्ष-84, नवीन भवन उ०प्र० सचिवालय लखनऊ में एक बैठक प्रस्तावित है जिसमें संघ के अधिकतम 02 प्रतिनिधियों द्वारा विचार/मत/सुझाव प्रदान किये जाने हेतु प्रतिभाग किया जाना है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त बैठक में ससमय प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by

PUSHPRAJ

Date: 08-06-2026

15:04:22

(पुष्पराज)

विशेष सचिव ।

संख्या-वे०आ०-2- ()/2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नवत् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- (2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(पुष्पराज)

विशेष सचिव ।

पंकज जैन
सदस्य सचिव
Pankaj Jain
Member Secretary



भारत सरकार
आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग
Government of India
Eighth Central Pay Commission

D.O No.35/6/2026-VST/8CPC

Dated the 27th May, 2026

Dear Sh. Goyal,

The Eighth Central Pay Commission is undertaking an assessment of the existing emolument structure and concerns of various categories of employees, pensioners and services as per its Terms of Reference

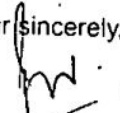
2. In order to better appreciate the concerns of the stakeholders in distant areas, ensure wider representation and get a first-hand impression about the functioning and conditions of various cadre/services, the Commission intends to hold meetings in various parts of the country and interact with interested stakeholders. Accordingly, the Commission has scheduled interactions in the state of Uttar Pradesh on **22-23 June, 2026** in **Lucknow**, where representatives of Unions/Associations, individuals as well as Institutions/organizations are likely to attend.

3. During the proposed visit, the Commission would also like to hear the State Government on their perspective relating to fiscal impact of earlier pay commissions on State Government and other issues of relevance. The State Government may like to share suggestions and good practises related to emolument structure, attracting talent in Government service, promoting efficiency and accountability in the work culture.

4. In so far as the Commission's visit is concerned, may I request the State Government to kindly consider extending protocol to the Commission and provide security at the venue for the smooth conduct of the interactions/meetings of the Commission in Hyderabad. It is also requested to kindly nominate a Nodal officer for facilitating the entire event. State level Associations of All India Service Officers may also kindly be informed if they wish to interact with the Commission. The venue of the event, travel details, meeting schedule, and delegation details shall be shared with the Nodal Officer in due course.

5. In case of any further details, your office may contact Shri Ravi Prakash Yadav, Deputy Secretary, at 9792478381 or ds2@8cpc.gov.in who shall be coordinating on behalf of Eighth Central Pay Commission.

With regards,

Your sincerely,

(Pankaj Jain)

Shri Shashi Prakash Goyal
Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
101, 'B' Block, Lok Bhawan, U.P. Secretariat,
Lucknow -226 001
Email: csup@nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-वे०आ०-2-154/दस-2026
लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2026

श्री शिव गोपाल सिंह, अध्यक्ष, उ०प्र० सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ लखनऊ, उ०प्र०।	श्री अर्जुन देव भारती , अध्यक्ष, उ०प्र० सचिवालय संघ,, उ०प्र०।	इ० हरिकिशोर तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०।	श्री एस०पी० तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०।
श्री जे०एन० तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०।	श्री सुरेश कुमार रावत, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ०प्र०।	श्री वी०पी० मिश्र, अध्यक्ष, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, उ०प्र०।	श्री रिजवान अहमद सिद्दीकी, अध्यक्ष, राजकीय वाहन चालक महासंघ, उ०प्र०।
श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० सरकार स्टेनोग्राफर्स महासंघ उ०प्र०।	श्री उग्रसेन सिंह, अध्यक्ष, उ०प्र० सांख्यिकीय सेवा परिसंघ उ०प्र०।	इ० एन०डी० द्विवेदी, अध्यक्ष, उ०प्र० डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ।	श्री कृतार्थ सिंह, अध्यक्ष, उ०प्र० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन।
श्री रामराज दूबे, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ।	श्री कमल अग्रवाल, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ।	इ० हृदय नारायण मिश्र, अध्यक्ष, उ०प्र० डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ।	श्री दिवाकर सिंह, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन।
श्री संदीप कुमार पाण्डेय, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन।	श्री राम लाल यादव , प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० कर्मचारी महासंघ।	श्री जे०पी० पाण्डेय, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन।	श्री अजय सिंह , प्रान्तीय अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ।

महोदय,

कृपया सदस्य सचिव, आठवों केन्द्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके साथ 18 प्रश्नों की प्रश्नावली संलग्न कर उन पर राज्य सरकार के अधिकारियों एवं अन्य का विचार/मत/सुझाव प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि --

The Commission have released a Questionnaire inviting public responses/views on the issues relevant to determining pay scales, pensions, monetary benefits and other service matters. The Questionnaire is available at MyGov.in portal/our website at 8cpc.gov.in Individuals, researchers, are be to respond and share their views. A copy of the Questionnaire is also attached.

Pay/emolument structure/service conditions of Central Government impact not just its own employees, but also those of many State Governments and other autonomous bodies/institutions/organizations. In addition, second order effects are usually seen on market wage structure as well.

The intention of this missive is to seek inputs/views on this Questionnaire from a larger cross section of society. You may perhaps like to bring the contents of this communication to officers of State Government and others so that they can share their views, if they so desire.

3- अतः आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2026 द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में आयोग की प्रश्नावली संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया प्रश्नावली में उल्लिखित बिन्दुओं पर यदि कोई विचार/सुझाव/मत प्रदान करना चाहते हैं तो निम्नलिखित वेबसाइट पर अपने विचार/सुझाव/मत व्यक्त करना चाहेंगे :-

For Employees/Pensioners/Individuals and Associations/Unions of serving employees/retirees
<https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/>

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by

PUSHPRAJ

Date: 10-03-2026

विशेष सचिव।
13:42:40

संख्या-वे०आ०-2- (1)/2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- (1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र (अंग्रेजी/हिन्दी) में प्रकाशित किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध अपर मुख्य सचिव महोदय से करना चाहें।

(पुष्पराज)

विशेष सचिव।

No. 6435/MS/SECY GI/2026

पंकज जैन

सदस्य सचिव

Pankaj Jain

Member Secretary



भारत सरकार
आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग
Government of India
Eighth Central Pay Commission

D.O No.10/12/2026-Estt/8CPC

13th February, 2026

Dear Sh. Goyal,

The Eighth Central Pay Commission have been constituted by the Government and is functioning now. The Commission would be undertaking an assessment of the emolument structure, including pay, allowances, etc of Central Government employees and other employees as per the mandate in its Terms of Reference and to make recommendations thereon.

19/1/सचि (BS)/26

VS (PR)

2. The Commission have released a Questionnaire inviting public responses/views on the issues relevant to determining pay scales, pensions, monetary benefits and other service matters. The Questionnaire is available at MyGov.in portal/our website at 8cpc.gov.in Individuals, researchers, are free to respond and share their views. A copy of the Questionnaire is also attached.

20.02.26

मवानी सिंह खगावेल

सचिव,

वित्त विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

Pay/emolument structure/service conditions of Central Government impact not just its own employees, but also those of many State Governments and other autonomous bodies/institutions/organizations. In addition, second order effects are usually seen on market wage structure as well.

सं. 9233/अनुसंधान/दत्त-सा/20.2.6

दिनांक: 19/02/26

The intention of this missive is to seek inputs/views on this Questionnaire from a larger cross section of society. You may perhaps like to bring the contents of this communication to officers of State Government and others so that they can share their views, if they so desire.

सचिव (BS)

With regards,

Acc. वित्त
उत्तर प्रदेश शासन

Your sincerely,

(Pankaj Jain)

19/02/2026

Encl. as above.

अपर मुख्य सचिव

वित्त एवं वित्त जायदत्त, संरक्षण वित्त
एवं बाह्य सहायता परिशोधना विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

D.S (PR)

80 VA-2

Shri Shashi Prakash Goyal
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh.

(एस.पी.के. गौयल)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

20-02-2026

विशेष सचिव

वित्त विभाग

सचिवालय, चण्दलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली / 7th Floor, Chanderlok Building, Janpath, New Delhi
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री नीपट वर्मा
20/2/26

D.O. Letter from Member-Secretary, 8th CPC

Kuldeep Meena Meena < kuldeep.meena@gov.in >

Tue, 17 Feb 2026 2:17:49 PM +0530

To "CHIEF UP"<csup@nic.in>

Cc "Member Secretary 8CPC"<membersecy-8cpc@gov.in>,"Manish Kr Kr"
<manish.kr1975@nic.in>

Respected Sir,

Greetings of the day!!!

Please find attached a copy of D.O letter dated 13.02.2026 from Member-Secretary, 8th CPC for kind consideration please.

Thanks & Regards

Kuldeep Singh Meena
Assistant Director
Eighth Central Pay Commission
☎:- +91-8233633073
website: 8cpc.gov.in

2 Attachment(s)

8CPC Questionnaire.pdf
79.4 KB

D.O letter to Government of Ut...
420.4 KB

(लक्ष्मी शर्मा)
सहायक सचिव
। नवम्बर १९९९

8th CPC QUESTIONNAIRE

For Employees/Pensioners/Individuals and Associations/Unions of serving employees/retirees

<https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/>

For Ministry/Department/UTs/Attached and Subordinate Offices/Organizations under Ministry/Department

<https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire-ministries-departments-and-uts/>

Q No.	Ques. for
Q1	<p>Implementation of the recommendations of a Pay Commission has macro economics impacts. Some of these are positive in terms of boost to consumption and savings whilst others are negative in terms of the higher fiscal deficit, inflationary potential & crowding out of other expenditure such as for overall development & public welfare. Decisions in this regard involve choices. Based on current state of the economy & the country's aspirations, what should be the guiding philosophy which must underpin the overall approach of the 8 CPC?</p>
Q2	<p>Pay determination in organisations including Government involves "horizontal relativity" i.e. for analogous posts across domains/cadres being placed in the same level/scale & "vertical relativity" i.e. on promotion, transition to a higher scale/band of pay. Relativity within different posts of Government has been broadly established over time. However, relativity/positioning between pay and perquisites in Government and the private sector is less established. How should the 8th CPC assess/evaluate relativity between pay & perquisites in Government and the public/private sector?</p>

Q3	Should 8 th CPC consider uniform horizontal relatively across all government departments, or should it consider sector-specific benchmarking where government functions are compared with their respective industry peers? For instance, should compensation for government engineers be benchmarked against private sector engineering firms, financial officers against the BFSI sector, and healthcare professionals against private healthcare? What would be the advantages and implementation considerations of such an approach?
Q4	Security of tenure, a training regimen, housing, leave encashment, predictable/increments, medical coverage, time bound progression, inflation indexed salary, retiral benefits are certain features associated with most jobs in Government. How should these be factored in while crafting a compensation matrix and relative positioning viz-a-vis the private sector?
Q5	Government employment is part of the organized sector. A far larger proportion of the job force is in the informal sector and the gig economy. What influence do you think entry level pay scales implemented by Government have on compensation practices in the informal or gig sector?
Q6	Salaries in Government have a distinct element of compensation for length of service (increment usually annual), an element of neutralization for changes in cost of living/inflation (dearness allowance) & an element for higher responsibilities based on seniority/merit/pay scale on promotion. In that context, what do you think the "fitment factor" adopted by Pay Commissions should represent? What should such a fitment factor principally aim at?
Q7	Salary of a Secretary in the Central Government typically represents the apex or the pinnacle i.e. the highest end of the scale. What should be the principle for determining this? Should there be a variable pay component for such position?
Q8	How can pay scales for all Group A Services be fixed so as to attract candidates of the requisite caliber? Should pay scales be more attractive at entry point or later, after a few years in service? What principles should guide such differentiation to ensure competitive positioning for talent-critical roles while maintaining fiscal prudence?
Q9	How should rates and frequency of increments in respect of different scales of pay be determined? Should these be uniform or vary across scales / time periods during service?

Q10	<p>Over course of time, many allowances have been introduced or rationalized based on specific nature of work, expenses such as on travel, compensation for hardship/risk/peculiarities associated with place of posting etc. Most of these are partially inflation indexed. An alternative approach has been the Cafeteria Approach followed by Central Public Sector Enterprises (CPSEs), wherein except for a handful of allowances, executives choose from a set of perquisites & allowances, subject to an overall ceiling of basic pay. Which approach do you think is more appropriate for Central Government employees?</p>
Q11	<p>The Seventh Pay Commission had assessed that in January, 2014, there were about 47 lakh serving Central Government personnel. This included CAPF, Railways & Defence forces. The number of pensioners was just short of 52 lakh. In 2025-26, the number of Central Government personnel stands at about 50 lakh, which the number of pensioners is almost 70 lakh. The increase in the number of pensions has created additional demands on Government's Budget. What approaches could help to satisfy reasonable expectations of pensioners whilst keeping the fiscal impact within manageable limits?</p>
Q12	<p>The Seventh Pay Commission was constituted in 2014 and implemented from 1.1.2016. The period since then has been marked by a lower trajectory of inflation, as compared to earlier decades. This is also reflected in the All India Consumer Price Index (Industrial Workers), which is used for DA calculation. Should the 8th CPC explore a hybrid indexation approach that factors in both inflation protection and formal sector wage growth trends? What proportion might be reasonable for each component, and what implementation considerations would arise? What are your expectations on inflation/CPI increase over the next 10 years?</p>
Q13	<p>Railways, CAPF and Defence forces typically account for about 70% of Central Government personnel. What particular considerations, monetary or non monetary should be factored in while determining their pay & allowances?</p>
Q14	<p>Scientists work in certain specialized streams/departments such as Department of Space, Department of Atomic Energy etc. What should be appropriate benchmarks to be kept in mind for fixing their emoluments?</p>
Q15	<p>Military Service Pay is currently admissible to personnel of Armed Forces. This was in recognition of the special nature of their duties. In that context and given the changing nature of their jobs, how should the pay of soldiers, sailors and airforce personnel be determined? How should it relate to the starting salary in Government or the pay of a constable in CAPF/ Police?</p>

Q16	<p>The nation has many more military pensioners than serving military personnel. In 2025-26, outgo on Defence Pensions is likely to be higher than the outgo on Defence salary and allowances. As overall defence pension bill increases, in line with projections, impact will be visible on equipment and arms purchase their maintenance and on modernization of defence forces. What changes would you recommend to contain increases in defence manpower costs and its pension bill?</p>
Q17	<p>Productivity Linked Bonus (PLB) is paid to some employees of Government such as Railways, Postal staff whilst Non-Productivity Linked Bonus is given to specified Central Government employees including some in Armed Forces. How can the Bonus structure be reimagined for rewarding excellence in productivity & performance? Should PLB/ Ad-hoc Bonus continue to be given on uniform basis (e.g. 60 days of salary for all) or be differentiated, based on individual performance?</p>
Q18	<p>Contractual appointments in the form of lateral entry have been tried during the last few years. Do you think this should be expanded and other practices such as part time work, fixed term employment, etc. introduced in Government at middle/ higher levels to tap a bigger talent pool? What could be the pros and cons of doing this?</p>

No physical copies/paper copies/emails of the responses are being considered/required by the Commission